



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 243      राँची, गुरुवार,      7 वैशाख, 1938 (श०)  
27 अप्रैल, 2017 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

24 अप्रैल, 2017

**संख्या-SUDA/AMRUT/CERC-GIS-MP/04/2017-2772** शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) प्रारंभ की गई है। झारखंड राज्य के वर्तमान में 07 शहर सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत तथा अन्य शहरों के लिए GIS Based मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

उपर्युक्त योजना अमृत के तहत मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा राज्य स्तर पर करने हेतु एक परामर्शी मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति (Consultancy Evaluation and Review Committee (CERC) का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र०	पदनाम	विभाग	उत्तरदायित्व/भूमिका
1	निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण,	नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2	मुख्य नगर निवेशक, TCPO	नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग	नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
4	निदेशक (परियोजना), जुडको	नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5	नगर आयुक्त/उपाध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी	संबंधित शहरी निकाय/प्राधिकार	सदस्य
6	तकनीकी पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता से अन्यून)	पथ निर्माण विभाग	सदस्य
7	उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
8	उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी	ऊर्जा विभाग	सदस्य
9	उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	सदस्य
10	TCPO, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
11	नगर निवेशक, TCPO	नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य-सचिव

2. उपरोक्त कमिटी अमृत शहर के साथ-साथ अन्य शहरों के लिए तैयार कराये जा रहे GIS Based मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेन्ट प्लान की समीक्षा कर, संबंधित परामर्शी को दिशा-निर्देश जारी करेगी। मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेन्ट प्लान की स्वीकृति/परिवर्तन से संबंधित समस्त कार्य विभाग स्तर उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

3. समिति, प्रत्येक समीक्षा बैठक के 03 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन/कार्यवाही विभाग को समर्पित करेगी। समीक्षा के दौरान परामर्शी एवं निकाय को दिये जाने वाले दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से समीक्षा कार्यवाही में अंकित किए जायेंगे।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,  
सरकार के प्रधान सचिव।